



वर्षा के बाद भी चुनावों में मतदान बढ़ेगा

केलकता। पूर्वोत्तर भारत में बसे पर्वतीय राज्य मजोरम के चुनावी तस्वीर सबसे अनूठी और दिलचस्प है। भले ही मुख्यधारा की मीडिया में उसे खास तवज्जो नहीं मलि रही हो, वहां का चुनावी मॉडल का कद्म आदर्श है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, राज्य में कहीं भी ज्यादा बैनर और पोस्टर नहीं नजर आते। इस बार के विधानसभा चुनाव भी अपवाद नहीं है। चर्च चुनावी भ्रष्टाचार पर कहीं नगिाह रखता है। चर्च का प्रतिनिधित्व करने वाले का संगठन के बैनर तले ही तमाम राजनीतिक दलों की रैलियों का आयोजन किया जाता है। किसी भी चुनाव से पहले चर्च पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तय कर देता है। यही वजह है कि राज्य में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले नहीं के बराबर होते हैं। यहां 25 नवंबर के मतदान होने हैं।

राज्य में चुनाव आयोग से ज्यादा असर मजोरम पीपुल्स फोरम (पीपीफ) का है। यह राज्य के सबसे बड़े चर्च संगठन सीनॉड का प्रतिनिधि है। हर बार की तरह इस बार भी पीपीफ ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए 27 नयिम बनाए हैं। फोरम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई राजनीतिक दल इन 27 में से किसी भी नयिम का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग भी पीपीफ के दिशानिर्देशों का समर्थन करता है।

मजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी अश्विनी कुमार कहते हैं कि हमारा और पीपीफ का मकसद समान है। वह है मुक्त और नष्पक्ष चुनावों का आयोजन। राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी कब और कहां चुनावी रैली करेगी, यह फैसला भी पीपीफ ही करता है। संगठन ने उम्मीदवारों के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने, सामुदायिक दावतों के आयोजन और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के चरित्र पर अंगुली उठाने पर भी रोक लगा दी है।

राजनीतिक विश्लेषक वानलालुते कहते हैं कि यहां चुनावी माहौल देश के दूसरे हिस्सों से अलग होता है। राजधानी आइजल में भी ज्यादा शोरगुल नहीं दिखाई देता। कुछ लोगों को लगता है कि मजोरम के चुनावी मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों में लागू कर चुनाव खर्च को कभी कम किया जा सकता है। लेकिन आइजल के पाछुंगा यूनिवर्सिटी कलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लालथालमुआना के नहीं लगता कि यह मॉडल दूसरे हिस्सों में प्रभावी होगा। वे कहते हैं कि किसी तटस्थ संगठन की देख-रेख में चलने वाले चुनाव अभियान का फायदा यह है कि मतदाताओं में पैसे बांटने के मामले सुनने को नहीं मलिते। लेकिन यह मॉडल दूसरे राज्यों में कम नहीं करेगा। वे कहते हैं कि राजनीति में धार्मिक संगठनों के हस्तक्षेप के दूसरे राज्यों में कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वीकार नहीं करेगी।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को उम्मीद है कि अबकी इन चुनावों में होने वाला मतदान पीपीफ के 90 फीसद मतदान का रिकॉर्ड तोड़ देगा। उनका कहना है कि राज्य का चुनावी माहौल देश के दूसरे हिस्सों के मुकबले अलग है। यहां आचार संहिता के उल्लंघन के इक्का-दुक्का मामले ही होते हैं। मजोरम में 1995 से ही शराबबंदी लागू है। लेकिन हर चुनाव में यहां शराब भी का प्रमुख मुद्दा बनती रही है। उम्मीदवारों पर वोटों को लुभाने के लिए शराब बांटने के आरोप लगते रहे हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद पीपीफ असम से चोरी-छिपे पहुंचने वाली शराब कई गुनी ऊंची कीमत पर बिकती है।

मजिोरम में सत्तारु कंग्रेस राज्य में दोबारा सत्ता में आने केला की-चोटी क जोर लगा रही है तो तीन पार्टियों क गठजो अबकी उसे हटा क सत्ता पर कब्जा जमाने क प्रयास क रहा है। कंग्रेस सरकार के अगुवा ललथनहवला अपनी सरकार के कमकज के सहारे वोट मांग रहे है तो मजिोरम नेशनल फ्रंट (म न फ), मजिोरम पीपुल्स कंग्रेस और मारालैड डेमोक्रेटिकफ्रंट वाला मजिोरम डेमोक्रेटिक लायंस स्थानीय मुद्दों के अपने जंडे में जगह देकर वोटों के लुभाने की केशशि क रही है। मजिोरम के मध्य में स्थिति सरचपि वधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पीयू ललथनहवला क बार फिर अपनी कस्मत आजमा रहे है। इस बार उनके वपिकी मजिोरम डेमोक्रेटिक लायंस (मडी) के उम्मीदवार सी लालरमजउवा से की टक्कर मलि रही है। ललथनहवला इस सीट से छह बार चुनाव जीत चुके है।

मजिोरम देश क अकेला ऐसा राज्य है जहां मतदाता सूची में भी महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकबले ज्यादा है। राज्य के लगभग 6.86 लाख वोटों में से 3.49 लाख महिला है और 3.36 लाख पुरुष। राज्य में सरकारी नौकरियों में लगभग 47 हजार महिला है। यानी कुल कर्मचारियों क 35-40 फीसद मतदाता सूची में पुरुषों पर भारी होने के बावजूद मजिोरम की राजनीति में महिला बेचारी ही है। मजिोरम और देश के दूसरे राज्यों में भले कई असमानता हों, क चीज में वह बाकी राज्यों के बराबर है। वह यह क दूसरे राज्यों की तरह यहां भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तमाम राजनीतिक दल महिलाओं के टिकट देने में बेहद कंजूसी बरतते है। यह हालत तब है जब सामाजिक जनजीवन में महिलाओं की भूमिक काफी अहम है। अबकी वधानसभा की 40 सीटों केला मैदान में उतरे 142 उम्मीदवारों में महज चार महिला है। बीते वधानसभा चुनावों में छह महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जीत सकी। पछिले 25 साल में कोई भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकी है।

देश के दूसरे राज्यों के मुकबले इस परवतीय राज्य के उम्मीदवारों की प्रोफाइल बेहतर है। मजिोरम वधानसभा की 40 सीटों केला मैदान में उतरे 142 उम्मीदवारों में आधे से अधिक करो पता है। नेशनल इलेक्शन वाच की ओर से जारी आंक के मुताबकि 142 उम्मीदवारों में 75 (53 फीसदी) करो पता है। उनमें से हर उम्मीदवारों के पास औसतन 2.31 करो रुप की संपत्ति है। इनमें 68 फीसद उम्मीदवार ग्रेजु ट है। सबसे अहम बात यह है क सरिफ तीन उम्मीदवारों के खलाफ ही आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में मजिोरम मॉडल पूरे देश केला क आदर्श साबति हो सकता है।